NAGAR NIGAM JAIPUR HETITAGE
Purara police mukhyala, Hawamahal ke piche, badi chopad, Jaipur

BID DOCUMENT

Operation for Ariel Hydraulic Platform ladder (42 meter)
Tender issuing form

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No</th>
<th>Particular</th>
<th>Detail</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Name of work</td>
<td>Operation for Ariel Hydraulic plate farm ladder (42 meter)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Cost of tender document (non-refundable)</td>
<td>Rs. 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>In favor of municipal corporation Jaipur, payable at Jaipur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Risl processing fee (non-refundable)</td>
<td>Rs. 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>In Favor of Managing Director RISL, payable at Jaipur</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Estimated project cost</td>
<td>Rs. 18 lacs</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Earnest money deposit (2 %)</td>
<td>Rs. 36,000</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Tender Publication on official web site <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a></td>
<td>21-08-2023, 05 PM</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Tender download start date</td>
<td>21-08-2023, 06 PM</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Bid Submission start date</td>
<td>25-08-2023, 05 PM</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>bid submission End date</td>
<td>31-08-2023, 04 PM</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Technical bid opening date/time</td>
<td>31-08-2023, 05 PM</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Signature of issuing officer

[Signature]
TERMS AND CONDITIONS FOR OPERATION AND MAINTAINANCE

1. Successful bidder shall execute the operation work of the machine as per instruction of JMC.

2. Scope of work includes deployment of machine with required manpower such as Trained and experienced Driver cum operator, at least two operators on the machine for 24 hours.

3. Tender document can be downloaded from the website www.eproc.rajasthan.gov.in. Tenders can be submitted through ONLINE only. Tenders in Physical form shall not be accepted.

4. All Bidders should submit Tender fee, Processing fee & EMD online to www.jaipurmc.org before last date & time of Bid submission and also scan the receipt and upload to www.eproc.rajasthan.gov.in.

5. The earnest money will be forfeited in the following cases:-
   (A) When the tenderer withdraws or modifies the offer after opening of tender but before acceptance of tender.
   (B) When tenderer does not execute the agreement in prescribed form within 15 days from the date of LOA/work order, whichever is issued first.
   (C) When the tenderer does not deposit the security money after the approval of tender within 15 days from the date of LOA/work order, whichever is issued first.

6. (A) Successful tenderer will have to execute an agreement in the prescribed form within a period of 07 days of LOA/Order and deposit security equal to 5% of the value of the stores for which tenders are accepted. The Corporation on the EMD/Security Money will pay no interest.
   (B) Security money shall be deposited in form of Demand Draft/Bank guarantee may be accepted issued by any schedule bank in favour of JMC. The Bank guarantee shall remain valid till the Operation period.

7. To facilitate evaluation of tenders, Corporation may, at its sole discretion, seek clarifications in writing from any tenderer regarding its Tender.

8. Machine shall be parked at JMC Fire station or any specified place.

[Signature]

\[3\]
9. This contract shall be valid for 1 year from the date of issuance of work order. Looking to the necessity, this may be extended for next year with mutual understanding between bidder and JMC.

10. The contractor has to begin the operation immediately after receipt of confirm order.

11. JMC shall not be responsible for any accident, mishap or damage caused by or in the machine or to the human being at the time of working as well as parking.

12. सफल निविदादाता द्वारा प्रतिमाह मैकेनिकल इनजिनियर से वाहन का निरीक्षण करवा कर वाहन का कार्यरत स्थिति में होने की रिपोर्ट बनाकर मुख्य अभिनिष्ठान अधिकारी को प्रतिमाह 15 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

13. निविदादाता द्वारा वाहन पर कार्यरत ड्राईवर कम ऑपरेटर के पीएफ व ईएसआई जमा का प्रमाण पत्र प्रतिष्ठा माह बिल के साथ मुख्य अभिनिष्ठान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा सभी कर्मचारियों के पीएफ व ईएसआई के लिए निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

14. परिमाण द्वारा उक्त मशीन (एयरियल हाइड्रोलिक लेडर फ्लेट फार्म वाहन संख्या RJ 14 EA 2181) का बीमा करवा कर संचालन हेतु सफल निविदादाता को सौपी जाएगी।

15. निविदादाता द्वारा एयरियल हाइड्रोलिक लेडर फ्लेटफार्म वाहन के ऑपरेशन हेतु लगाये जाने वाले ऑपरेटर द्वारा आदेशों की अवहेतना करने व निर्देशित कार्य नहीं करने पर तथा नशे आदि की स्थिति में पाये जाने पर मुख्य अभिनिष्ठान अधिकारी द्वारा ऑपरेटर को तुरंत प्रभाव से कार्य से हटा दिया जावेगा तथा उक्त ऑपरेटर के स्थान पर अन्य ऑपरेटर की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। व्यवस्था नहीं करने पर निविदादाता से ₹ 5,000/- की शाश्त्री वसूली जावेगी।

16. निविदादाता की उक्त वाहन के साथ दिये गये सामान, वाहन की देख रेख व सुरक्षा आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अगर कोई सामान चोरी या गुम होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा उसकी पूर्ति तुरंत करनी होगी। पूर्ति नहीं करने पर निविदादाता से पेनल्टी सहित उक्त की कीमत वसूल की जावेगी।

17. निविदादाता यदि कार्य करने में असफल रहता है तो प्रतिदिन ₹ 5000/- की शाश्त्री वसूली की जावेगी।
18. एरियल हाइड्रोलिक लेफ्टर प्लेटफार्म का संचालन कार्य निविदादाता को 24 घण्टे करना होगा।

19. कार्य की सुदृढ़ व्यवस्था की दृष्टि से समय-समय पर निगम द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु निविदादाता बाध्य होगा।

20. कोई भी ज्योिन्ट वेन्चर स्वीकार योग्य नहीं होगा।

21. वाहन/मशीन की दुर्घटना होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसारों के लिए फॉर्म स्वेय जिम्मेदार होगी। इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के क्लेम/दायित्वों के लिए नगर निगम जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त महाद्य न का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

23. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में जयपुर न्यायिक क्षेत्र होगा।

24. निविदादाता को निविदा की सभी शर्तें स्वीकार करनी होंगी। निविदादाता की ओर से प्रस्तुत सत्यता निविदाएं निरस्त की जा सकती हैं।

25. निविदा में आरटीपीएफ एक्ट के नियम लागू होंगे।

26. निविदादाता द्वारा एनेक्सचर A, B, C, D, E को स्वभाविक हस्ताक्षर कर स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा।

27. Bid Validity 90 Days (3 month) होगी।

Signature of Bidder

Dy. Commissioner (Fire)
Nagar Nigam Jaipur Heritage
Operation for Ariel Hydraulic Platform ladder (42 meter)

ELIGIBILITY CRITERIA

1. बोलिदाता फर्म का फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धि प्रमाण पत्र सलंगन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. बोलिदाता फर्म के मालिक/फर्म का पैन कार्ड सलंगन करना आवश्यक होगा।
3. पूर्व में फर्म का किसी राजकीय विभाग/निगम/बोर्ड आदि द्वारा दोषी मानकर काली सूची में नहीं ढाला गया है। इस आशय का 100 रुपये के नौन ज्यूडिशियल स्टेम में नोटरी प्रबंधिक से सत्यापित शापथ पत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. बोलिदाता फर्म के प्रोप्राइटर को चरित्र प्रमाण पत्र 100 रु. के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाकर देना होगा।
5. ज्वोइट बेन्नर स्वीकार नहीं होगा।
6. बोलिदाताओं को निविदा शुल्क, अभावता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन नगर निगम जयपुर की बेव्साइट www.jaipurmcheritage.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली स्वीड को स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा। नियत समय के पश्चात प्राप्त बोलिदाताओं पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त सभी प्रक्रिया नेट (ई—टेलर्संग) से करनी होगी।
7. बोलिदाता द्वारा निविदा प्रपत्र तथा एनेक्सचर A, B, C, D, E को स्वयं हस्ताक्षर कर स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही बोली को मान्य किया जायेगा।
8. बोलिदाता का पीडीएफ/ईससैट /जीएसटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र सलंगन करना आवश्यक होगा।
9. बोली में अधिकृत विवेक की बोली आती है तो अन्य बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. बोलिदाता को उक्त कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signature of Bidder

Dy. Commissioner (Fire)
Nagar Nigam Jaipur Heritage
## NAGAR NIGAM JAIPUR HERITAGE

Purara police mukhyala, Hawamahal ke piche, badi chopad, Jaipur

### Operation for Ariel Hydraulic plate farm ladder (42 meter)

#### Financial Proposal

<table>
<thead>
<tr>
<th>S. No.</th>
<th>Particular</th>
<th>Approved Rate</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Operation for Ariel Hydraulic plate farm ladder (42 meter)</td>
<td>Rs............... per machine per month</td>
</tr>
</tbody>
</table>

All Taxes are included in bidding rate.

---

**Signature of Bidder**

**Dy. Commissioner (Fire)**

Nagar Nigam Jaipur Heritage
Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party’s performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.
Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ............... for procurement of ................. in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: 
Place: 
Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Doc1
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal
(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker’s cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal
(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall—
   (i) hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.
FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No ...........of ..............
Before the ......................... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against
   and name and designation of the officer / authority
   who passed the order (enclose copy), or a
   statement of a decision, action or omission of
   the Procuring Entity in contravention to the provisions
   of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented
   by a representative, the name and postal address
   of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
   .................................................................
   ................................................................. (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   .................................................................
   .................................................................

Place ..............................................
Date ..............................................
Appellant's Signature
Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity’s Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.
Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause
(a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from time to time by the Government, but the Government shall not be liable to pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.

(c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.

(d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.

(e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors.

(f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff
The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:

(a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.

(b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.

(c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.
Clause 3:
The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code
The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:
Near Relatives barred from tendering
The Contractor shall not be permitted to tender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared in valid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years
No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor’s service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control
The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:
The work (whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,
temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer- in -charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts or God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the “G” Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor’s bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor’s bill, can be recovered from the contractor’s bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:
The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum be appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.